

>

Title: Regarding recognizing institutes under National Institute of Design to work on Assistive Technology for making many health related products in the country.

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली): अध्यक्ष जी, आपने मुझे बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया है । आज वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे है और मुझे लगता है कि इस दिन पॉलिसी इंटरवेंशन की आवश्यकता है और पालिसी इंटरवेंशन में मुझे प्वाइंटेड तरीके से असिस्टिव टेक्नोलॉजीज के बारे में कुछ कहना है । असिस्टिव टेक्नोलॉजी सबसे अधिक महत्व का विषय है । एडल्ट डायपर्स और अन्य ऐसा सामान है, जिसकी आवश्यकता पड़ती है और उम्र बढ़ने पर भी इन चीजों की जरूरत पड़ती है । दुख का विषय यह है कि हम ऐसी ज्यादातर चीजें इम्पोर्ट कर रहे हैं । हमारी कानपुर बेस्ड कम्पनी इसमें आज भी अच्छा काम कर रही है लेकिन इसकी जरूरत कहीं अधिक है । जरूरत अधिक होने के कारण मेरा मानना है कि मेक इन इंडिया के तहत यदि हम एमएसएमई सैक्टर, स्किल इंडिया और हेल्थ मिनिस्ट्री की तमाम योजनाओं को एक हार्मोनियस तरीके से आपस में मिलाएं और एक ग्रुप ज्वाइंट सैक्रेटरीज का बनाएं, तो उसके कारण न केवल भारत अपनी भरपाई कर पाएगा, बल्कि विदेशों में भी इस सामान का निर्यात कर पाएगा और सबसे बड़ी दिक्कत असिस्टिव टेक्नोलॉजी के स्टैंडर्डिजेशन प्रोसेस की है । बीआईएस जैसी एजेंसी को इसकी असिस्टेंस के लिए लगाया जाए और उसकी स्टैंडर्डिजेशन के लिए और टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन के माध्यम से, आर एंड डी के माध्यम से हमें आईआईटी और ऐसे किसी संस्थान को काम देना चाहिए । नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन का बिल पिछले हफ्ते ही आया है । मेरा मानना है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन में किसी एक इंस्टीट्यूट को रिकग्नाइज करके असिस्टिव टेक्नोलॉजी की यूनीवर्सल डिजाइनिंग पर काम किया जाना चाहिए और भारत इसमें बहुत तरक्की कर सकता है और पूरी दुनिया की जरूरत को भी पूरा कर सकता है ।

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा, डॉ. निशिकांत दुबे, श्री सुधीर गुप्ता और श्री रोड़मल नागर को श्रीमती मीनाक्षी लेखी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।